राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 540/2009

बलविंदर सिंह

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री एच.एस. सिद्धू

श्री प्रदीप सिंह खोसा

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री सरवन कुमार

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

16/04/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत 08.01.2004 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/3) से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया था। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिसे 07.03.2005 के आदेश (अनुलग्नक पी/5) द्वारा खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर समीक्षा याचिका दायर की, जिसे भी 10.11.2008 के आदेश (अनुलग्नक पी/7) द्वारा खारिज कर दिया गया।

2. मामले के सुसंगत तथ्य यह हैं कि जब याचिकाकर्ता हेडमास्टर के पद पर था, तो उसे सीसीए नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप-पत्र दिया गया था (अनुलग्नक पी/1)।

2.1 याचिकाकर्ता ने आरोप-पत्र का जवाब दाखिल किया, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर ध्यान दिए बिना और दस्तावेजों पर विचार किए बिना, दिनांक 08.01.2004 को आक्षेपित आदेश पारित कर दिया (अनुलग्नक पी/3)।

2.2 याचिकाकर्ता ने दिनांक 08.01.2004 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध अपील दायर की, जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 07.03.2005 के नॉन-स्पीकिंग आदेश (अनुलग्नक पी/5) में खारिज कर दिया।

2.3 दिनांक 07.03.2005 के आदेश से व्यथित होकर माननीय राज्यपाल के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की गई, जिसे दिनांक 10.11.2008 के नॉन-स्पीकिंग आदेश (अनुलग्नक पी/7) द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः याचिकाकर्ता ने यह याचिका प्रस्तुत की है।

3. उत्तर में दिया गया बचाव यह है कि इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है, तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश केस रिकॉर्ड के आधार पर तथा याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात सही तरीके से जारी किया गया है। अपीलीय प्राधिकारी तथा समीक्षा प्राधिकारी ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को सही तरीके से बरकरार रखा।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वकीलों की प्रतिस्पर्धी दलीलें सुनी हैं, केस फाइल का अवलोकन किया है, और अब मैं आगामी पैराग्राफ में अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

5. सबसे पहले, रिट याचिका को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 27.01.2009 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया था, जो कि समीचीन है, उक्त आदेश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार जांच के अधीन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 8 जनवरी, 2004 को दंड का आदेश दिया गया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील भी 7 मार्च, 2005 को खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समीक्षा याचिका भी 10 नवंबर, 2008 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई। दंड लगाने वाले आदेश और पुष्टि के आगे के आदेशों की वैधता पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए निश्चित आरोपों के खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, कारणों द्वारा

समर्थित निष्कर्ष एक अर्ध-न्यायिक/न्यायिक आदेश में वस्तुनिष्ठता रखता है और तत्काल मामले में, ऐसे कारण स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि अपीलीय प्राधिकारी या समीक्षा प्राधिकारी द्वारा बाद में कारणों को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी या समीक्षा प्राधिकारी मूल आदेश में मौजूद खामियों को दूर नहीं कर सकते।

स्वीकार करें।

नोटिस जारी करें।"

6. उक्त आदेश बिना किसी जवाबी हलफनामे या प्रासंगिक समय पर दायर याचिका के उत्तर के पारित किया गया था। इसके बाद, रिट याचिका का विस्तृत उत्तर दायर किया गया।

7. दिलचस्प बात यह है कि उत्तर में इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त आदेश में दर्ज टिप्पणियों और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उसमें उल्लेखित प्रस्तुतियों के बारे में स्पष्ट रूप से चुप्पी है।

8. जैसा भी हो, उत्तर को पढ़ने से जो बात उभर कर आती है वह यह है कि बचाव पक्ष यह है कि एक बार जब दोषी कर्मचारी (यहां याचिकाकर्ता) को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था, तो अनुशासन अधिकारी सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत दिनांक 08.01.2004 को दंड आदेश पारित करने के लिए स्वविवेकाधीन था। "विवेक" शब्द को प्रतिवादियों द्वारा पूरी तरह से गलत समझा गया है, जैसे कि इसका प्रयोग बिना किसी कारण दर्ज किए किया गया हो।

9. विवादित आदेश का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि यह जितना संभव हो सकता है, उतना ही रहस्यमय है।

10. इसमें केवल इतना कहा गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अभिलेख का अवलोकन करने और तर्कों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को दोषी पाया है, और इसलिए उसे दण्ड दिया गया।

11. कम से कम यह कहा जा सकता है कि ऐसा आदेश न केवल विवेक का दुरुपयोग है, बल्कि यह न्यायालय को भी पूरी तरह से असमंजस में डाल देता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के मन में ऐसा क्या विचार आया कि वह दोषी कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का दोषी ठहराने के निष्कर्ष पर पहुंचा?

12. निस्संदेह, बाद में अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी ने महसूस किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में विवेक का अभाव था और उन्होंने दण्ड आदेश में कारण जोड़ने का प्रयास किया। यह वस्तुओं को उल्टे सीधे क्रम में रखने के समान है और इसलिए यह कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

13. मैं यहां यह भी जोड़ना चाहूंगा कि आदेश के तर्क को सुधारने के लिए बाद में किया गया कोई भी प्रयास दोषी कर्मचारी को अपना बचाव करने में असुविधा में डाल देगा, क्योंकि वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाएगा, और अपीलीय प्राधिकारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी की जगह लेने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा कोई उपाय स्वीकार्य नहीं है।

14. मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप, तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश को आगामी परिणामों के साथ रद्द किया जाता है। वेतन के बकाया की गणना सेवा नियमों के अनुसार देय ब्याज के साथ की जाएगी।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।